नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत

01 घंटा 27 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया भाषण | **25** करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला | **30** लाख करोड़ रुपए युवाओं को मुद्रा योजना के तहत दिया ऋण | **70** रिफॉर्म हमारी सरकार ने अब तक किए | **04** करोड़ गरीबों को दिए घर, बिजली, पानी, सिलेंडर

नई दिल्ली, 05 फरवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा. प्रधानमंत्री ने एक घंटा 27 मिनट भाषण दिया. उन्होंने कहा कि लोकसभा में राष्ट्रपति के संबोधन पर चर्चा नहीं हो सकी. यह संविधान का अपमान है, आदिवासी परिवार से आई महिला राष्ट्रपति का अपमान है. विपक्ष को संविधान शब्द बोलने का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा लोकसभा में चेयर पर कागज फेंके गए. बड़ी दर्दनाक थी. कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत कूट-कूट कर भरी हुई है. देश की जनता भलीभांति यह देख रही है.

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि मोदी अभी तक प्रधानमंत्री कैसे बना हुआ है, ये कांग्रेस पचा नहीं पा रही है. कांग्रेस शासनकाल में एक भी ट्रेड डील किसी देश के साथ नहीं हुआ. मोदी ने कहा कि जिस पर लाखों करोड़ों माताओं बहनों का रक्षा कवच हो, उसकी कब्र तुम कभी नहीं खोद पाओगे. हमने सिंधु का पानी रोका...आतंकियों को घर में घुसकर मारा... इसलिए ये हमारी कब्र खोदते हैं. कांग्रेस को लगता है पीएम का पद, उनकी जागीर है. उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे लिए सेवा का माध्यम है. कांग्रेस की सरकार रिमोट से चलती थी. हमारी सरकार 140 करोड़ लोगों के रिमोट से चलती है. चोरी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है. इन लोगों ने गुजराती सरनेम गांधी को भी चुरा लिया.

खुद को राजा मानने वाले राहुल गांधी असमानता की बात करते हैं. कांग्रेस के पीएम ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन किया कुछ नहीं. घुसपैठिये हमारे नौजवानों की नौकरी छीन रहे हैं और कांग्रेस उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस पर दबाव बना रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर शायरी अंदाज में हमला बोलते हुए कहा कि तुम दुनिया को कितना धोखा दोगे. आईना देखोगे तो चेहरा कहां छिपाओगे, सच्चाई सामने आ जाएगी. (शेष पेज 9 पर)

पीएम मोदी के संबोधन की बड़ी बातें...

- कांग्रेस सरकार में बैंकिंग व्यवस्था में तबाही थी.
- कांग्रेस के राज में अर्थव्यवस्था तबाह थी. हमने सुधार किया.
- कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया. देश को पीछे धकेला.
- चार लाख करोड़ किसानों के खातों में पहुचाएं रुपए.
- नीति आयोग योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है.
- आज पीएसयू रिकार्ड लाभ की स्थिति में है.
- पूरे देश में बस्तर ओलंपिक की हो रही है चर्चा.
- दस करोड़ किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम जमीन है.
- दुनिया में भारत के टैलेंट की मांग बढ़ी है.
- एलआईसी आज सर्वोच्च स्तर पर है.
- टीएमसी घुसपैठियों की वकालत कर रही है.

पीएम मोदी पर हमला कर सकते थे कांग्रेस सांसद : बिरला

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने पीएम को सदन में आने से मना किया था. उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस के सांसद उन पर शारीरिक हमला कर सकते थे. अंत में उनकी स्पीच के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूर करने का फैसला हुआ. लोकसभा की कार्यवाही को शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.

भारत टैक्सी सेवा का उद्घाटन!

मोहन भागवत का तीन दिवसीय दौरा

- मेरठ में 19-21 फरवरी को करेंगे विशेष संवाद

नागपुर, 05 फरवरी. आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक मेरठ में तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. 19 फरवरी की शाम वह मेरठ पहुंचेंगे और 21 फरवरी की शाम प्रस्थान करेंगे.

इस दौरान उनका मुख्य उद्देश्य खेल जगत, किसान, शिक्षाविद और उद्यमी वर्ग से संवाद स्थापित करना है. शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 20 फरवरी को माधवकुंज के सामने मैदान में विशेष संवाद गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा.

एक नजर में

सुको ने अनुराग ठाकुर पर लगा प्रतिबंध हटाया

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे उन्हें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मामलों में भाग लेने और पद संभालने की अनुमति मिल गई है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ ने श्री ठाकुर की ओर से दायर एक याचिका पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया. उन्होंने ने 2017 में अदालत द्वारा जारी एक निर्देश को वापस लेने की मांग की थी. गौरतलब है कि जनवरी 2017 में, उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने से संबंधित निर्देशों का पालन न करने के कारण पद से हटा दिया था. उस आदेश के निर्देश में विशेष रूप से दोनों पदाधिकारियों को बीसीसीआई का कोई भी कार्य करने से रोक दिया गया था.

कोयला खदान में धमाके से 16 मजदूरों की मौत

शिलांग. मेघालय की एक कोयला खदान में गुरुवार को भीषण धमाका हुआ, जिसकी वजह से 16 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, जिस खदान में भीषण धमाका हुआ है, वो अवैध है. यह घटना ताशखाई में एक कोयला खनन स्थल पर हुई, जहां कथित तौर पर हुए एक जोरदार धमाके के बाद हादसा हुआ. घटना के बाद राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया. वहीं, अधिकारी धमाके के सही कारण की जांच कर रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, मारे गए मजदूर असम निवासी हो सकते हैं. उनमें से एक पीड़ित की पहचान कटीगारा के बिहारा गांव के निवासी के तौर पर हुई है.

आरएसी टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं : रेल समिति

- संसदीय समिति ने कहा नियम बनाया जाए
- यात्री बिना कन्फर्म बर्थ यात्रा करने को हैं मजबूर

नई दिल्ली, 05 फरवरी. देश में लंबी दूरी के लिए किफायती सफर करना हो तो ट्रेन सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. यही वजह है कि ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई बार कंफर्म सीट नहीं मिलती और आरएसी टिकट से ही सफर करना पड़ता है.

आरएसी टिकट पर भी यात्रियों को पूरा किराया देना पड़ता है. ऐसे में एक संसदीय समिति ने कहा कि आरएसी (रिजर्वेशन अगेनेस्ट कैंसिलेशन) टिकट पर पूरा किराया वसूलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें यात्रियों को पक्की सीट नहीं मिलती और कई बार उन्हें बिना कन्फर्म बर्थ के सफर करना पड़ता है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी (पीएसी) ने कहा कि जिन यात्रियों को चार्ट बन जाने के बाद भी कंफर्म बर्थ नहीं मिलती और वे आरएसी में ही यात्रा करते हैं, उनसे पूरा किराया नहीं लिया जाना चाहिए. समिति ने सुझाव दिया कि रेलवे मंत्रालय को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, जिसमें यात्रियों को कुछ किराया वापस मिल सके.

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली, 05 फरवरी. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सिविल सेवा परीक्षा (प्रीलिम्स)- 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार 933 वैकेंसी निकाली गई हैं. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक किया जा सकता है. इस बार वैकेंसी पिछले साल से कम है. पिछले वर्ष यूपीएससी सीएसई में 979 वैकेंसी थीं. इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस समेत विभिन्न सिविल सेवाओं में जाना चाह रहे युवा 24 फरवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं.

वैचारिक स्तर पर भारत को हिंदुत्व पर गर्व

हरिद्वार में संत सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

भारत माता मंदिर समाज और राष्ट्र में कर रहा ऊर्जा का संचार

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 5 फरवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सनातन संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाने में आदि शंकराचार्य का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. मप्र की धरा से आदि शंकराचार्य जी का विशेष संबंध रहा है. वैचारिक स्तर पर भारत को हिंदुत्व पर गर्व है, हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है.

सनातन की धारा शाश्वत रूप से बहती रहे, इस उद्देश्य से संतवृंद और सरकार समन्वित रूप से प्रयासरत है. हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर समाज और राष्ट्र में ऊर्जा का संचार कर रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित गुरुदेव समाधि मंदिर मूर्ति स्थापना समारोह के तहत संत सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.

इस अवसर पर जूनापीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महाराज ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव को सिंहस्थ-2028 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं.

संत महात्माओं को दिया सिंहस्थ-2028 का निमंत्रण: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के संवाहक, वैदिक सनातन संस्कृति के उन्नायक, देश के प्रथम भारत माता मंदिर के संस्थापक पद्मभूषण स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उन्हें नमन किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार भव्य और दिव्य सिंहस्थ के आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाओं और विकास कार्यों पर ध्यान दे रही है.

(शेष पेज 9 पर)

भलाई छोड़ दूसरे तथ्यों पर हो विचार

बच्चे की हिरासत के मामले में फैसला रद्द

नई दिल्ली, 05 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि बच्चे की हिरासत का फैसला सिर्फ बच्चे की भलाई पर आधारित नहीं हो सकता, बल्कि अदालतों को कई दूसरे जरूरी तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए, जिसमें माता-पिता का व्यवहार, उनकी वित्तीय क्षमता, रहन-सहन का मानक और बच्चों का आराम तथा शिक्षा शामिल हैं.

शीर्ष न्यायालय ने गुरुवार को जम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें उच्च न्यायालय दो नाबालिग बच्चों की हिरासत उनकी मां को वापस दे दी थी. न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायाधीश एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि हिरासत का अंतिम आदेश देते समय अदालत के सामने कई दूसरे तथ्य भी होते हैं. यह अपील एक तलाकशुदा जोड़े (दोनों भारतीय नागरिक हैं) के बीच 2017 और 2019 में पैदा हुए उनके दो नाबालिग बच्चों की हिरासत को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद से जुड़ा था. शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से गुणों के आधार पर विचार करने के लिए भेज दिया.

बीजापुर मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर

बीजापुर, 05 फरवरी. छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में गुरुवार सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. इस सशस्त्र संघर्ष में एक नक्सली मारा गया है तथा एक एके-47 राइफल बरामद की गई है. मुठभेड़ अब भी जारी है. पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीजापुर जिले के दक्षिणी क्षेत्र में सशस्त्र नक्सलियों की मौजूदगगी की विश्वसनीय सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने एक व्यापक खोजी अभियान शुरू किया.

भारत किसी से भी तेल लेने के लिए आजाद

- पुतिन के दूत ने दे दी बड़ी छूट
- ट्रंप के दावे पर मॉस्को का आया जवाब

मॉस्को, 05 फरवरी. भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद मॉस्को ने रूसी तेल की भारतीय खरीद पर बयान दिया है. क्रेमलिन ने बुधवार को कहा कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए आजाद है.

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को खारिज करते हुए कहा कि कच्चे तेल की आपूर्ति को डाइवर्सिफाई करने के भारत के फैसले में कुछ भी नया नहीं है. इसके पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा, रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पाद सप्लाई करने वाला अकेला देश नहीं है और न कभी रहा है.

पेसकोव ने कहा, भारत ने हमेशा दूसरे देशों से ये प्रोडक्ट्स खरीदे हैं. इसलिए हमें इसमें कुछ भी नया नहीं दिखता. वहीं, रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि भारत की रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और मॉस्को अपने संबंध और गहरे करने के लिए तैयार है.

खुशखबरी गृहमंत्री अमित शाह ने कहा-ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों को मिलेगी कड़ी टक्कर

देश में पहली सरकारी 'भारत टैक्सी ऐप' लॉन्च

नई दिल्ली, 05 फरवरी . देश की पहली को-ऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी ऐप आज आधिकारिक तौर लॉन्च हो गई है. सहकारिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई ये नई कैब सर्विस सीधे तौर पर ओला-उबर और रैपिडो जैसे प्राइवेट राइड-हेलिंग कंपनियों के मोनोपोली को चुनौती देगी. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन में भारत टैक्सी को ऑफिशियली लॉन्च किया है.

खास बात ये है कि ये पूरी तरह ऐप बेस्ड स्वदेशी टैक्सी सर्विस है. माना जा रहा है कि इसके आने से ओला, उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियों को कड़ी टक्कर मिलेगी और कॉम्पटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा आम ग्राहकों को मिल सकेगा. ड्राइवर-ओनरशिप मॉडल पर बेस्ड भारत टैक्सी ऐप कमिशन फ्री सर्विसेज उपलब्ध कराएगा, जिससे कैब चालकों को उनके हक का पूरा पैसा मिलेगा.

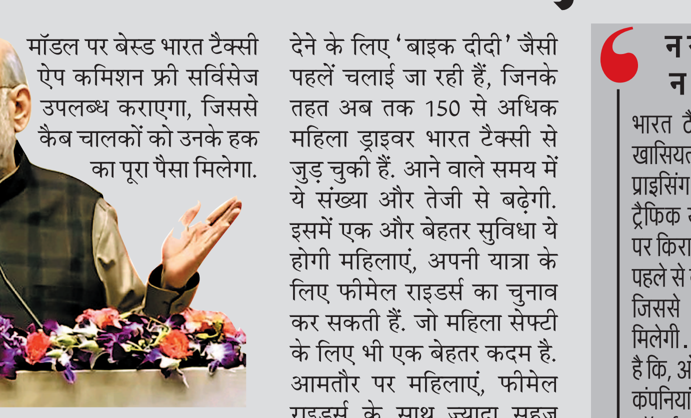

महिलाओं के लिए फीमेल राइडर्स: भारत टैक्सी सर्विस में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'बाइक दीदी' जैसी पहलें चलाई जा रही हैं, जिनके तहत अब तक 150 से अधिक महिला ड्राइवर भारत टैक्सी से जुड़ चुकी हैं. आने वाले समय में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी. इसमें एक और बेहतर सुविधा ये होगी महिलाएं, अपनी यात्रा के लिए फीमेल राइडर्स का चुनाव कर सकती हैं. जो महिला सेफ्टी के लिए भी एक बेहतर कदम है. आमतौर पर महिलाएं, फीमेल राइडर्स के साथ ज्यादा सहज महसूस करती हैं. भारत टैक्सी के जरिए लोग ऑटो, कार और बाइक टैक्सी बुक कर सकेंगे.

न सर्ज प्राइसिंग न छुपा किराया

भारत टैक्सी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी. बारिश, ट्रैफिक या पीक टाइम के नाम पर किराया नहीं बढ़ेगा. किराया पहले से तय और पारदर्शी होगा, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी. आमतौर पर देखा जाता है कि, ओला-उबर जैसी प्राइवेट कंपनियां खराब मौसम या पीक ऑवर्स में दोगुना किराया वसूलती है, लेकिन भारत टैक्सी के साथ ऐसा नहीं होगा.

अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन गिरफ्तार

फरीदाबाद, 05 फरवरी. अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दिकी को कथित धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जहां से पुलिस को चार दिन की हिरासत मिली है.

करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का है आरोप

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सिद्दिकी पर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप हैं. पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है. यह कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है, जब यूनिवर्सिटी पहले से ही कई केंद्रीय एजेंसियों की जांच का सामना कर रही है.